जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

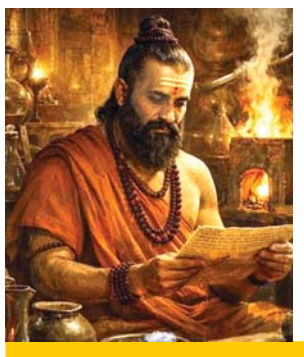

The World's First Chemistry Lab

Nagarjuna's method of refining and polishing gold and silver created a brilliant finish, this process laid the foundation for modern metalworking

The Song That Changed Indian Cinema Forever

The flute player managed somehow, keeping his instrument above water. But the tabla and harmonium players faced a greater challenge

'राजस्थान के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एस पी शर्मा को तुरंत हटाया जाए'

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत से इस बारे में आग्रह किया और जस्टिस शर्मा पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से आग्रह किया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए किसी अन्य राज्य से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाए।

"बार एंड बैंच" के पास उपलब्ध 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को लिखे पत्रों में न्यायमूर्ति मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा पर आरोप लगाया है कि वे धनी मुकदमेबाजों के पक्ष में मामलों की सूची (केस लिस्टिंग) में हेरफेर कर रहे हैं और अगले महीने होने वाली अपनी सेवानिवृत्ति से पहले प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

- **2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को लिखे पत्र में जस्टिस मेहता ने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा रसूखदार और संपन्न मुकदमे बाजों के पक्ष में केस लिस्टिंग में हेरफेर कर रहे हैं और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस शर्मा अगले माह रिटायर होने वाले हैं।**
- **जस्टिस मेहता खुद राजस्थान हाई कोर्ट से हैं और 9 नवम्बर 2023 से सुप्रीम कोर्ट में हैं। जस्टिस मेहता ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों ने मुझ से जस्टिस शर्मा की शिकायत की है कि वे अक्सर अपने साथी जजों को धमकाते हैं और सीजेआई सूर्यकांत से निकटता का दावा करते हैं।**

न्यायमूर्ति मेहता स्वयं राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 30 मई 2011 को राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। फरवरी 2023 में उन्हें गोंहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इसके बाद 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया।

न्यायमूर्ति शर्मा को नवंबर 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 2022 में उनका तबादला पटना हाई कोर्ट कर दिया गया।

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जब उन्होंने राजस्थान वापस भेजे जाने का अनुरोध किया, तब तत्कालीन सीजेआई "डीवाई चंद्रचूड़" की अध्यक्षता वाले कोलीजियम ने मार्च 2023 में उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और इसके बजाय, उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया। मई 2025 में एक नए कोलीजियम प्रस्ताव में उन्हें राजस्थान वापस भेजने की सिफारिश की गई। इसके बाद वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति मेहता के पत्र के अनुसार, वे अब पिछले 10 महीनों से अधिक समय से इस पद पर हैं।

2 अगस्त के अपने पहले पत्र में न्यायमूर्ति मेहता ने लिखा कि राजस्थान के दौरे के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के अनेक न्यायाधीशों ने मुझसे मुलाकात की और न्यायमूर्ति एसपी शर्मा के व्यवहार को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति शर्मा अक्सर अपने साथी न्यायाधीशों को बदले की कार्रवाई, जिसमें तबादला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुग्राम के व्यस्ततम इफ्को चौक की सड़क धँसी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश के बाद, गुरुग्राम के व्यस्त इफ्को चौक पर एक महत्वपूर्ण सड़क धंस गई, जिससे जमीन के नीचे बने इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबे समय से चली आ रही कमजोरियां सामने आ गईं। सड़क धंसने के पीछे गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) की देखरेख वाली एक बड़ी सीवर लाइन को जिम्मेदार माना जा रहा है।

- **भारी बारिश के बाद हुए इस हादसे ने सड़क निर्माण की खामियों को उजागर कर दिया है। सड़क धँसने के लिए उसके नीचे से गुज़र रही सीवर लाइन को जिम्मेदार बताया गया है।**

यातायात पुलिस ने वाहन दुर्घटनाएं रोकने के लिए तुरंत अस्थायी बैरिकेड लगा दिए। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नगर निगम के इंजीनियरों को बुलाया गया।

थोड़ी देर की बारिश के बावजूद, शहर का ड्रेनेज सिस्टम तुरंत ठप हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें कब समाप्त होंगी?

यह भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही पार्लियामैंट्री बोर्ड में भी फेरबदल होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। भाजपा के लिए समय तेजी से निकल रहा है। 2027-28 में लगातार होने वाले 16 विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू होने में अब करीब 180 दिन बाकी हैं। अकेले 2027 में ही पार्टी को गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत, पांच राज्यों में अपनी सत्ता बचानी है। इसके अलावा उसका लक्ष्य पंजाब में आप और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से हटाना भी है।

पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, नेतृत्व मोदी युग के "अब तक के सबसे बड़े रीसेट" की तैयारी में है, जिसमें कई नए लोगों को शामिल करने, कुछ को बाहर करने और संगठन तथा सरकार में व्यापक बदलाव किए जाने की संभावना है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मामला केवल युवाओं या ऊंची जातियों जैसे प्रमुख वोट वर्गों के खिसकने, या महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं है, जो पार्टी को परेशान कर रहे हैं। हिंदुत्व की लहर भी कमज़ोर हुई है। फिलहाल यह धारणा मजबूत होती दिख रही है कि समस्याओं को हल करने के लिए हमारे पास नए विचार नहीं हैं। मामूली कॉस्मेटिक बदलाव काम नहीं करेंगे। बड़े नीतिगत और राजनीतिक प्रयास की तत्काल जरूरत है और उस प्रयास को संभालने के लिए पार्टी तथा सरकार का पुनर्गठन पहला कदम हो सकता है। एक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहिए।"

- **पार्लियामैंट्री बोर्ड में बदलाव के लिए संघ का भी भारी दबाव है। संघ इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल करना चाहता है।**
- **अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामैंट्री बोर्ड से बाहर करने के साथ ही यह नियम बनाया गया था कि इसमें मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया जाएगा। तर्क था कि मुख्यमंत्रियों से जुड़े फैसले मुख्यमंत्री कैसे ले सकते हैं।**
- **पर, अब चूँकि आरएसएस का दबाव है, ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि संसदीय बोर्ड से किसे हटाया जाए?**

यह लगभग तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के करीब 27 महीने पूरे होने के बाद, 2014 के बाद पहली बार भाजपा एक साथ कई नकारात्मक धारणाओं और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रही है। इस स्थिति में, पार्टी कमज़ोर या अस्पष्ट संकेत भेजने का जोखिम नहीं उठा सकती।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम ने एक सप्ताह पहले संगठन में जो बदलाव किए, उनसे ऐसा संकेत मिला कि "पिक्चर अभी बाकी है।"

यह एक सामान्य संगठनात्मक फेरबदल जैसा था, जिसमें कई पहलू शामिल थे। अच्छे रिकॉर्ड वाले भरोसेमंद नेताओं को बरकरार रखा गया, जबकि सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ पुराने और नए चेहरों को शामिल किया गया। लेकिन सूची में छिपे संकेतों को समझने के लिए उसका इतना बारीकी से विश्लेषण करना पड़ा।

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी स्तर पर "संसदीय बोर्ड जैसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने वीज़ा अपॉइन्टमैंस पर रोक लगाई

वॉशिंगटन से प्राप्त खबर के अनुसार, अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी वीज़ा रद्द करने की कार्यवाही करने जा रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में वीज़ा अपॉइन्टमैंट रोक दिए हैं या उनका समय बदल दिया है। यह कदम वाइट हाउस में रिपब्लिकन नेता के दूसरे कार्यकाल के दौरान जारी इमिग्रेशन पर सख़्ती के बीच उठाया गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, वीज़ा सेवाओं के लिए अपॉइन्टमैंट इसलिए रोके गए हैं ताकि विदेशों में मौजूद सभी राजनयिक केन्द्रों पर ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा सके।

- **अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एक एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर से देश भर में 2 लाख विदेशी नागरिकों के वीज़ा रद्द किए जा सकते हैं।**
- **वीज़ा अपॉइन्मैंट रोकने और उनका समय बदलने का यह कदम ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत उठाया गया है।**
- **हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, वीज़ा अपॉइन्टमैंट इसलिए रोके गए ताकि विदेशों में मौजूद सभी राजनयिक केन्द्रों पर ग्लोबल ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा सके।**

वॉशिंगटन से एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रशासन अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर वीज़ा रद्द करने की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक एग्ज़िक्यूटिव ऑर्डर के तहत देशभर में 2 लाख तक विदेशी नागरिकों के वीज़ा रद्द किए जा सकते हैं।

कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या की

कोटा, 26 अगस्त (निसं)। कोटा में एक कोचिंग छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। घटना कुन्हाड़ी इलाके की है, छात्रा अपनी बहन के साथ फ्लैट में रहती थी।

घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके फ्लैट को सीज़ कर दिया। छात्रा के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। उसके परिजन भी कोटा पहुंच गए। छात्रा मूल रूप से मध्यप्रदेश के छतरपुर की निवासी थी।

- **छात्रा कुन्हाड़ी में अपनी बहन के साथ फ्लैट में रह रही थी तथा मैडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी।**

कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि 20 वर्षीय छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी तथा उसकी छोटी बहन उसके साथ ही रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल में अचानक आई बाढ़ में 105 भारतीय पर्यटक लापता

भारत ने बाढ़ दुखांतिका के लिए नेपाल को हरसंभव सहायता देने का वादा किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। नेपाल के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से बात की और भारत की ओर से नेपाल को हरसंभव मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस कठिन समय में भारत के लोग नेपाल के अपने बहन-भाइयों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत बचाव और राहत अभियानों के लिए नेपाल के साथ निकटता से समन्वय कर रहा है।

बुधवार को तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सीमा के दूसरी ओर तिब्बत में भी बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के एक क्रॉसिंग पर भूस्खलन के बाद पड़ोसी काउंटी जिरोंग में कुछ लोग लापता हैं।

- **भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की। बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर खेद जताया।**
- **नेपाल पर्यटन विभाग के अनुसार, लद्दाख के समीप भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से कई लोग लापता हैं, इनमें 291 पर्यटक और 93 नेपाली हैं। 291 यात्रियों में से 105 भारतीय, 37 एनआरआई हैं। शेष अमेरिका, मलेशिया, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व नीदरलैंड्स के हैं।**

बुधवार को तिब्बत सीमा से लगे रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लापता करीब 400 लोगों में कम से कम 105 भारतीय शामिल हैं। इनमें से अधिकांश लोग तिब्बत में होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 9 बजे (स्थानीय समय) तिब्बत की ओर से आने वाली भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इससे ति ब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिलों, तथा काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिले में भारी नुकसान हुआ।

"नेपाल पर्यटन बोर्ड" के एक बयान के अनुसार, रसुवा में आई बाढ़ के कारण कुल 384 यात्री लापता हैं। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं।

लापता यात्रियों में 105 भारतीय पर्यटक और 37 एनआरआई शामिल हैं। बाकी पर्यटक अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स से हैं।

बुधवार को भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वह नेपाल में किसी भी राहत एवं बचाव अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के अनुसार विनाशकारी बाढ़ के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक दो सप्ताह बढ़ी

जयपुर, 26 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल वन में विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई अंतरिम रोक को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

- **विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब पेश करने के लिए समय दिया।**

इसके साथ ही अदालत ने मामले में जवाब पेश करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को समय दिया है। जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। अदालत ने करीब एक माह पहले बोर्ड को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए, नियुक्ति पत्र जारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सभी प्रयासों के बाद भी ग्रोथ उस गति से क्यों नहीं बढ़ रही, जैसी उम्मीद की जाती है

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का व्यय कभी भी निजी निवेश का स्थान नहीं ले सकता?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 अगस्त। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अप्रैल-जून तिमाही में धीमी होकर 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना है, लेकिन इस आंकड़े के पीछे बड़ी चिंता यह है कि निजी कंपनियां नए निवेश के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर आगे आने से हिचक रही हैं।

समस्या केवल कंपनियों के पास नकदी की कमी की नहीं है। कंपनियां इसलिए भी सावधानी बरत रही हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की मांग को लेकर पर्याप्त भरोसा नहीं है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक (जिओपोलिटिकल) अनिश्चितता, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, व्यापार से जुड़े जोखिम और सस्ते इम्पोर्ट से कॉम्पिटिशन नए निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर असर डाल रहे है।

"रॉयटर्स" के 58 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो जनवरी-मार्च तिमाही की 7.8 प्रतिशत दर से कम है। आधिकारिक आंकड़े 31 अगस्त को जारी होने हैं। इस दर के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि मौजूदा तिमाही में विकास दर और घटकर 6.6 प्रतिशत और उसके बाद की तिमाही में 6.5 प्रतिशत रह सकती है।

मुख्य कमज़ोरी प्राइवेट कैपिटल इन्वैस्टमैंट साइकल का व्यापक न होना है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पिछले साल की दूसरी छमाही से निजी निवेश में शुरुआती सुधार दिखाई दिया है, लेकिन अभी तक यह इतना मजबूत, टिकाऊ और व्यापक नहीं हुआ है कि इसे निवेश में बड़ी और स्थायी तेजी कहा जा सके।

- **जब निजी निवेश होता है तो वह वाकई में ग्रोथ का संकेत माना जाता है, क्योंकि उद्योगपति इन्वैस्टमैंट तब करता है, जब उसे लगता है कि मार्केट बढ़ रहा है और उसे महसूस होता है कि बढ़ती माँग की पूर्ति के लिए उसे और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी।**
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास ग्रोथ का संकेत नहीं होता, निजी उद्योग लगाना अवश्य ग्रोथ का संकेत होता है।**
- **निजी कंपनियाँ नए इन्वैस्टमैंट से हिचक रही हैं, इसका कारण यह नहीं है कि उनके पास पूँजी का अभाव है, असल में उन्हें भविष्य की माँग को लेकर पर्याप्त भरोसा नहीं है।**

कंपनियां पीछे क्यों हट रही हैं? पहली बड़ी बाधा डिमांड के बारे में साफ जानकारी न होना है। कंपनियां तभी निवेश करती है, जब उन्हें भरोसा होता है कि अतिरिक्त कारखाने, मशीनरी या उत्पादन क्षमता कई वर्षों तक पर्याप्त लाभ देगी। हालांकि उपभोक्ता मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन अलग-अलग आय वर्गों और क्षेत्रों में मांग एक जैसी नहीं है। इससे कंपनियां बड़े और ऐसे निवेश करने में हिचक रही हैं, जिन्हें बदला न जा सके, और जो इस धारणा पर आधारित हों कि आज की डिमांड आगे भी इसी तरह बनी रहेगी।

यह बात खास तौर पर उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सीधे उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। अगर कंपनियों को यह भरोसा नहीं है कि परिवार आगे भी मौजूदा स्तर पर खर्च करना जारी रखेंगे, तो वे नए कारखाने बनाने के बजाय मौजूदा कारखानों का इस्तेमाल बढ़ा सकती हैं। कॉरपोरेट निवेश के हालिया विश्लेषणों से यह भी पता चला है कि नए प्रोजेक्ट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और मैटल्स जैसे क्षेत्रों में केन्द्रित है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में व्यापक विस्तार नहीं हो रहा है।

दूसरी समस्या ग्लोबल और जिआपोलिटिकल अनिश्चितता है। अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। इससे ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुँचे

न्यूयॉर्क (अमेरिका), 26 अगस्त। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मंगलवार को अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में यहां पहुंचे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने डॉ. भागवत का स्वागत किया। संघ प्रमुख की यह यात्रा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है।

- **मैडिकल स्क्वायर गार्डन में सभा को संबोधित किया**

संघ प्रमुख भागवत के कार्यक्रम की मेजबानी अहेड फोरम (अमेरिकन हिंदूज फार एंगेजमेंट एंड डायलाग फोरम) कर रहा है। अहेड फोरम ने एक्स पर कहा, "इस कार्यक्रम का संदेश शाश्वत और सार्वभौमिक है कि दुनिया एक परिवार है। यह हमें बनावटी विभाजनों और मतभेदों से ऊपर उठने, मानवता को जोड़ने वाले बंधनों को पहचानने और आपसी सम्मान, सद्भाव व एकता की भावना को अपनाने का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)